



जब भी कभी समुद्र में बड़ा तूफान आता है, स्वाभाविक तौर पर पक्षी उससे दूर रहते हैं। सी बर्ड्स तो तूफानों से बचने के लिए सैकड़ों मील की अतिरिक्त दूरी भी तय कर लेती हैं। लेकिन हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ नैशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे एक शोध में एक आश्चर्यजनक बात पता चली है। कुछ सी बर्ड्स तूफान में सरवाइव करने के लिए अचानक उड़ती अपनी जाती हैं। जो सी पी. एस. ट्रैकर्स के इस्तेमाल से वैज्ञानिकों ने जापान के आवाशीमा आइलैंड पर प्रजनन करने वाली 401 स्त्रीकड शिअरवॉटर्स (शोर बर्ड्स की एक प्रजाति) की 11 साल तक निगरानी की। इनमें से 75 पक्षी उन्हें ऐसे मिले जो खराब मौसम होने पर सीधे टायफून में घुस गए। सह शोध लेखक, एमिली शैपर्ड, जो वेल्स में स्नान सी युनिवर्सिटी में एनिमल मूवमेंट की एक्सपर्ट हैं, का कहना है कि, यह शोध पत्र तूफान में जानवरों का सबसे बड़ा ट्रैकिंग डेटा सैट है। जिन पक्षियों को ट्रैक किया गया उन्होंने आठ घंटे तक तूफान का सामना किया। शैपर्ड ने बताया, "हमने जो देखा उस पर हमें यकीन नहीं हुआ। हमें कुछ अंदाज था कि, पक्षी कैसा व्यवहार कर सकते हैं, पर हमने जो देखा वैसा तो हमें किसी ने नहीं बताया था।" अधिकांश पक्षी, जिनका उन्होंने अध्ययन किया, जमीन के आसपास ही भोजन तलाशने वाले पक्षी थे। लेकिन जब ये पक्षी तूफान में फंसे तो जमीन पर जाने की बजाय सीधे तूफान की तरफ गए। शोध के अनुसार शिअरवॉटर्स की तूफान के केंद्र की तरफ जाने की संभावना ज्यादा देखी गई। मुख्य शोध लेखक, एमानुएल लैम्पीडाकिस के अनुसार "तूफान के समय एक समय ऐसा आता है जब पक्षियों की उड़ने की रफ्तार हवा की रफ्तार से कम रह जाती है तब पक्षी हवा के साथ बहने लगते हैं।" शिअरवॉटर्स हवादार वातावरण के आदी होते हैं। ये पानी के ऊपर रहते हैं, जहां तेज हवा के साथ वे बिना पंख फड़फड़ाए लंबी दूरी तय कर लेते हैं इससे उनकी ऊर्जा बचती है। लेकिन जमीन पर रहना उनके लिए मुश्किल होता है, यहां से उन्हें उड़ान भरने में मुश्किल होती है और परभक्षी पक्षियों का शिकार बनने का खतरा होता है। हालांकि ये प्रजनन के लिए तट पर आते हैं, पर अधिकांश समय महासागरों के ऊपर ही बिताते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि, तूफान की वजह से तट पर चल रही वे हवाओं से बचने के लिए ये पक्षी तूफान की तरफ उड़ान भरते हैं। उनके लिए जमीन पर रहने की बजाय तूफान की तरफ उड़ना ज्यादा सुरक्षित होता है।

समूचे उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठण्ड का दौर

नई दिल्ली, 8 जनवरी (वार्ता)। उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है वहीं दक्षिण भारत में जगह-जगह बारिश होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जबरदस्त शीतलहर के बीच रविवार को सबसे सर्द सुबह दर्ज किया गया। इसके साथ ही एन.सी.आर. इलाके में भी जनजीवन प्रभावित रहा।

मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में अगले चार दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। झारखंड के साथ-साथ बिहार में भी ठंडी हवायें चल रही हैं।

उत्तराखंड के चमोली जनपद अन्तर्गत, जोशीमठ में भूधंसाव के कारणों को तलाश रहे विशेषज्ञों के अनुसार, जोशीमठ की धरती हर साल 85 मिलीमीटर की गति से खिसक रही है। दूसरी ओर, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, भू धंसाव की यह स्थिति अचानक इस साल नहीं, अपितु पचास से अधिक वर्षों से लगातार बनी हुई है।

राज्य सरकार द्वारा जोशीमठ मामले के परीक्षण को गठित वैज्ञानिकों के दल में शामिल देहरादून स्थित

■ दिल्ली में रविवार इस सीजन का सबसे सर्द दिन व सुबह दर्ज किया गया।

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की वरिष्ठ विज्ञानी डा. स्वप्निमिता के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र का सेटलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया। जिससे पता चला कि यहां का भूभाग प्रति वर्ष 85 मिलीमीटर की दर से खिसक रहा है। उन्होंने बताया कि उत्पत्ति के समय से ही हिमालय के खिसकने की दर सालाना 40 मिलीमीटर के करीब है। सरकारी दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि इस क्षेत्र में भू धंसाव अथवा इमारतों में दरार पड़ने की शुरुआत पचास से भी वर्षों पूर्व हो चुकी थी।

बीच तेलंगाना के आदिलाबाद में शनिवार और रविवार को दरमियानी रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रामगुंडम में इसी अवधि के दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और मेडक में 11 डिग्री सेल्सियस के साथ दर्ज किया गया। राजधानी हैदराबाद का न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विभाग के मुताबिक राज्य में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

‘राहुल गांधी का करिश्मा काम करना शुरु कर चुका है’

तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है

नई दिल्ली, 8 जनवरी। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है। भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का करिश्मा काम करना शुरू कर चुका है और उन्हें लोगों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। टी.एम.सी. सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी है। उनका व्यक्तित्व युवाओं के लिए ज्ञान का प्रतीक बन गया है। देश ने इससे पहले ऐसी कोई यात्रा नहीं देखी। उनका लक्ष्य अच्छा है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हालांकि मैं टी.एम.सी. का नेता हूं और मेरी लीडर सही मान्यते में ममता बनर्जी हैं।

■ शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी को लोगों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी है, उनका व्यक्तित्व युवाओं के लिए ज्ञान का प्रतीक बन गया है। देश ने इससे पहले ऐसी कोई यात्रा नहीं देखी। उनका लक्ष्य अच्छा है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

■ उन्होंने कहा, इस यात्रा से उनकी छवि बदली है। इससे पहले एल.के.आडवाणी और चंद्रशेखर ने भी यात्रा निकाली थी। लेकिन यह भारत जोड़ो यात्रा बेमिसाल है, इसमें हर महजब के लोग शामिल हो रहे हैं।

मैं उनका हिमायती हूं, उनका प्रशंसक हूं। लेकिन कुछ बातों से नजर नहीं चुराई जा सकती। यूथ आइकन राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा से युवाओं की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हो गए हैं।

इस यात्रा से उनकी छवि बदली है। इससे पहले एल.के. आडवाणी और चंद्रशेखर ने भी यात्रा निकाली थी। लेकिन यह भारत जोड़ो यात्रा बेमिसाल

है। इसमें हर महजब के लोग शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जब ये बोला जाता है कि मैं नफरत बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो ये अच्छी बात है मैं उनको कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उनकी यात्रा सवाल भी उठाए गए, उनकी टीशर्ट से लेकर उनके लुक तक पर सवाल उठे, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देना व दोस्त बनाना शुरु किया

अफगानिस्तान सरकार ने चीन की कंपनी को देश के एक हिस्से में कूड ऑयल खनन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है

पांच नागरिक थे।

तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया, "तेल खनन के सौदे के तहत शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोल और गैस कंपनी (सी.ए.पी.ई.आई.सी.) अमू दरिया बेसिन में ड्रिलिंग करेगी।"

अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार है। सालों तक संघर्ष चलते रहने के कारण अफगानिस्तान को इस संपदा का इस्तेमाल नहीं हो सका है।

कई जानकारों का कहना है कि इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो सकता

■ चीन ने इसे दोनों देशों के लिए अहम प्रोजेक्ट बताया है। माना जा रहा है कि, ये ठेका हासिल करने के बाद इस इलाके में चीन की आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

■ साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तबसे किसी विदेशी फर्म के साथ तेल खनन का ये पहला बड़ा समझौता है। अभी तक दुनिया की किसी सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है।

हाल में चीन ने भी इसे एक अहम समझौता बताया है। अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू ने काबुल में हुई एक प्रेस

‘जोशीमठ में हर साल 85 एम.एम. नीचे धंस रही है जमीन’

सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार, भू-धंसाव की यह स्थिति अचानक नहीं, अपितु पचास साल से अधिक वर्षों से है

देहरादून/चमोली, 8 जनवरी (वार्ता)। उत्तराखंड के चमोली जनपद अन्तर्गत, जोशीमठ में भूधंसाव के कारणों को तलाश रहे विशेषज्ञों के अनुसार, जोशीमठ की धरती हर साल 85 मिलीमीटर की गति से खिसक रही है। दूसरी ओर, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, भू धंसाव की यह स्थिति अचानक इस साल नहीं, अपितु पचास से अधिक वर्षों से लगातार बनी हुई है।

राज्य सरकार द्वारा जोशीमठ मामले के परीक्षण को गठित वैज्ञानिकों के दल में शामिल देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की वरिष्ठ विज्ञानी डा. स्वप्निमिता के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र का सेटलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया। जिससे पता चला कि यहां का भूभाग प्रति वर्ष 85 मिलीमीटर की दर से खिसक रहा है। उन्होंने बताया कि उत्पत्ति के समय से ही हिमालय के खिसकने की दर

■ जोशीमठ में जमीन एवं मकानों में दरारें पड़ने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय में रविवार दोपहर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में जोशीमठ को डैंगर जोन घोषित करके वहां की स्थिति को बचाने एवं सुधारने का फैसला लिया गया।

सालाना 40 मिलीमीटर के करीब है। उन्होंने बताया कि यहां एक बार फिर इसका सर्वेक्षण किया जा सकता है, ताकि वर्तमान स्थिति का बेहतर आंकलन किया जा सके।

जोशीमठ में जमीन एवं मकानों में दरारें पड़ने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय में रविवार दोपहर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने यह बैठक बुलाई थी जिसमें कैबिनेट सचिव जॉर्ज गोबा, गृह सचिव, केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के

साथ इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा जोशीमठ के जिलाधिकारी सम्मिलित हुए। वहीं दूसरी ओर, सरकारी दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि इस क्षेत्र में भू धंसाव अथवा इमारतों में दरार पड़ने की शुरुआत पचास से भी वर्षों पूर्व हो चुकी थी। चमोली के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने बताया कि आठ अप्रैल 1976 को गढ़वाल के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पीयूष गोयल अमेरिका जायेंगे

नई दिल्ली, 8 जनवरी (वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नौ से 11 जनवरी तक अमेरिका की सरकारी यात्रा पर रहेंगे और वहां न्यूयार्क एवं वाशिंगटन में भारत-अमेरिका व्यापार पॉलिसी फोरम में हिस्सा लेंगे। आज यहां जारी आधिकारिक बयान में यह

■ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नौ से 11 जनवरी तक अमेरिका की सरकारी यात्रा पर रहेंगे और वहां भारत-अमेरिका व्यापार पॉलिसी फोरम में शामिल होंगे।

जानकारी दी गयी। गोयल यात्रा के पहले चरण में कन्वेंटिओनल इवेंट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत करेंगे और व्यापारिक नेताओं के साथ गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे तथा न्यूयार्क में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ओल्ड पैशन स्कीम 10 साल बाद देश को कंगाल कर देगी’

जाने-माने अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब राजस्थान समेत कई राज्य इसे लागू करने की कवायद में जुटे हैं

नई दिल्ली, 8 जनवरी। विभिन्न राज्यों में इस समय न्यू पैशन स्कीम (एन.पी.एस.) को हटाकर इसकी जगह ओल्ड पैशन स्कीम (ओ.पी.एस.) लागू करने की कवायद चल रही है। वोट बैंक की राजनीति के चलते इसके दुष्प्रभाव का विश्लेषण किये बगैर राजस्थान व हिमाचल सहित कई राज्यों ने ओ.पी.एस. लागू करने की घोषणा कर दी है। इस मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वित्तीय सलाहकार रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कहना है कि, "जो लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नतीजा ये होगा कि 10 साल बाद वित्तीय कंगाली आयेगी। मेरा मानना है कि ये कदम बेतुका है और वित्तीय कंगाली का कारण बन सकता है।"

अहलूवालिया ने ये बयान ऐसे वक्त दिया है, जब हिमाचल समेत कुछ राज्यों में हुए चुनावों में ओल्ड पैशन स्कीम को राजनीतिक दलों ने मुद्दा बनाया। कई राज्य सरकारों ने ओल्ड पैशन स्कीम को बहाल भी किया है। अहलूवालिया के हालिया बयान को लेकर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं जबकि

■ ओल्ड पैशन स्कीम (ओ.पी.एस.) कई राज्यों में चुनावी मुद्दा बनी हुई है, राजस्थान व छत्तीसगढ़ सरकार इसे लागू करने की कवायद में लगी हुई है। हिमाचल में नवनिर्वाचित सरकार भी ओ.पी.एस. लागू करने की घोषणा कर चुकी है।

■ आहलूवालिया पहले भी ओल्ड पैशन स्कीम की आलोचना कर चुके हैं और इसे सबसे बड़ी रेवडी और बेतुकी कवायद बता चुके हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की है। अहलूवालिया पहले भी ओल्ड पैशन स्कीम की आलोचना कर चुके हैं और इसे सबसे बड़ी रेवडी बता चुके हैं। एक कार्यक्रम में मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, "एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों और सत्ताधारी पार्टियों को चाहिए कि वो सिस्टम को ऐसे कदम उठाने से रोके जो निश्चित रूप से वित्तीय तबाही का सबब होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन ये कैसे किया जाए? जनता को बड़े पैमाने पर ये समझाने की जरूरत है कि भविष्य में

इसकी कितनी क्रीमत चुकानी पड़ेगी। मान लीजिए सरकार आपको ऐसी पैशन स्कीम दे रही है जो पहले से बेहतर है तो लोग इसे पसंद करेंगे। लेकिन कोई इसकी क्रीमत चुका रहा है। इसलिए हमें ऐसा जनमानस बनाने पर ध्यान देना होगा।"

अहलूवालिया ने कहा, "राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग इसकी क्रीमत चुकाते हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए और अगर राजनीतिक सिस्टम ये करने में अक्षम है तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है।"

उन्होंने कहा, "इसी तरह की चीजें अन्य देशों में भी होती हैं और हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कई देश राजनीतिक

तौर पर गैरजिम्मेदाराना फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसमें सुधार की भी गुंजाइश होती है। समस्या ये है और मुझे शंका है कि इस तरह के कदम उठाने को लेकर केंद्र सरकार पर कांपी दबाव होगा चाहे कोई भी सरकार हो।" रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी तो क्या होगा असर?

मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि सुधारों का मुख्य दारोमदार राज्यों पर होता है और बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जिनके लिए केंद्र को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती।

उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए राज्य के कानून के मुताबिक कई मामलों में अपराधीकरण को खत्म करने के लिए केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। केंद्र ऐसा करने से राज्य को नहीं रोकता है। लेकिन राज्य नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजों की लंबी सूची बना सकते हैं जो पूरी तरह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।"

उन्होंने कहा, "इस लिहाज से देखें तो सिर्फ पैशन स्कीम ही नहीं, बल्कि बिजली दरों को तय करने का मामला भी पूरी तरह राज्य के अधिकार में है, केंद्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)